



नई शिक्षा नीति 2020: सशक्त मानव पूंजी का उद्भव और चुनौतियां

उर्मिल वत्स¹, सुश्री लवी वत्स²

¹ राजनीति विज्ञान विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

² अनुसंधान विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली, भारत

सारांश

एक अच्छी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का आधार है।

21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है। एशिया में भी भारत की तरफ ही दुनिया की नजर है। भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत तरक्की की है। चाहे साइंस का क्षेत्र है, औद्योगिक उत्पादन हो, कोरोना काल में वैक्सीन बनाना हो, विधि क्षेत्र इत्यादि में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है, किसी भी राष्ट्र व समाज की प्रगति इस बात पर आंकी जाती है कि वहां पर मानव पूंजी का विकास सूचकांक क्या है? यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास सशक्त मानव पूंजी हो ! मनुष्य को अगर जीवित रहना है तो उसे जिस प्रकार भोजन चाहिए उसी प्रकार राष्ट्र को अगर सशक्त बनाना है, प्रगति के पथ पर निरंतर चलना है तो उसे सशक्त मानव पूंजी चाहिए ! इसी दिशा में माननीय सद्गुणों के पूर्णतया विकास, बच्चों के पालन-पोषण, उनके चरित्र निर्माण व उनके समाज के उत्थान में राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है 1968 में सबसे पहले शिक्षा नीति बनाई गई थी स फिर 1986 और 1992 में इसको संशोधित किया गया! 2020 की शिक्षा पद्धति से पहले जो नीतियां थी और उन नीतियों में शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए था वह कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था! एक रटने की प्रवृत्ति अधिक लग रही थी ! 2020 की शिक्षा पद्धति में इससे निजात पाने की कोशिश की गई है ! अब देखना यह है कि धरातल पर असली जामा पहनाने के लिए हमें किन किन चुनौतियों से निपटना होगा।

मूल शब्द: नई शिक्षा नीति 2020, सामाजिक मूल्य, कौशल विकास व चुनौतियां

“उठो जागो और तब तक न रुको जब तक हमें अपनी मजिल प्राप्त न हो जाए

“स्वामी विवेकानंद”

शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा जीवन है शिक्षा वह शस्त्र है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है स यह वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकास होता है स इसी के साथ विकास होता है समाज, देश और दुनिया का, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी और उसने सरकार के समक्ष जो स्वरूप प्रस्तुत किया था। उसे सरकार ने मंजूरी दी है। अब 2022-23 से इसे धरातल पर उतारा जा रहा है, उच्च शिक्षा नीति में उन सभी पहलुओं का ख्याल रखा गया जो समिति ने सुझाव रखे थे। इस नीति के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षा की रूपरेखा के आधार पर ही उच्च शिक्षा में मेडिकल की शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है स क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है स वर्चुअल लैब टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जिससे संपूर्ण विकास हो सके। वोकेशनल शिक्षा को स्कूलों और उच्च शिक्षा में इस तरह से समायोजित किया गया कि कम से कम 50: विद्यार्थी 2050 तक इसका लाभ उठा सकेंगे स बैचलर डिग्री भी बहुविषक होगी स इसके माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है स इसी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है कि शिक्षा की पहुंच विशेष वर्ग तक ना रहे बल्कि हर बच्चा एक कौशल विकास के साथ आगे बढ़े भारत को महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से 2020 की शिक्षा पद्धति में अहम बदलाव किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचनात्मक रचना व शिक्षा नीति का क्रियान्वयन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा पद्धति है जो 1968 और 1986 की शिक्षा नीति का पूर्ण से बदलाव है स एमएचआरडी ने 2017 में एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता डॉ के कस्तूरीरंगन ने की स इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया और जुलाई 29, 2020 को सरकार द्वारा इसको पास कर दिया गया स लगभग दो लाख सुझाव इस नीति के पक्ष और विपक्ष में प्राप्त हुए स इसमें स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 पर आधारित है जो कि 10+2 के स्थान पर है स मूलभूत चरण 3 से 8 वर्ष की आयु तक रहेगा। इसमें प्री स्कूल से दूसरी कक्षा तक, सेकंड 8 से 11 वर्ष की आयु तक, जिसको तैयारी चरण कहा गया है। तीसरी से पांचवी कक्षा तक, इसमें क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में किसी भी विषय को बखूबी समझ सकता है तीसरा 12 से 14 वर्ष की आयु मध्य चरण कक्षा 6 से 8 तक, इसमें किसी भी विषय का वैकल्पिक और रिपोर्ट कार्ड बच्चे की एकेडमिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। 15 से 18 वर्ष की आयु कक्षा 9 से 12 तक, माध्यमिक चरण पूरे भारत में समस्त पैटर्न केवल एक ही बोर्ड होगा स साइंस, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य विभाग अलग से नहीं होंगे सब विद्यार्थी सब पढ़ सकेंगे उच्च शिक्षा के ढांचे की बात करें तो यह 3 और 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होगा स लेकिन अगर 1 वर्ष के पश्चात छोड़ना चाहे तो उसे यह सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष के पश्चात डिप्लोमा 3 वर्ष के पश्चात डिग्री, 4 वर्ष के पश्चात मल्टीडिसीप्लिनरी बैचलर डिग्री विद रिसर्च बनाया जाएगा स जिसके आधार पर उच्च शिक्षा में डिग्री प्रदान की जाएगी। मास्टर डिग्री 1 या 2 साल की होगी स पीएचडी के लिए पहले मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री रिसर्च करने होगी। प्रत्येक जिले में या उसके पास कॉलेज और विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा जहां अंतर विषय पढ़ाए जाएंगे स नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जहां से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जाएगी स संस्थाओं को स्वायत्तता मिलेगी स उस शिक्षा में तीन तरह की

संस्थाएं होगी स एक रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटी,सेकंड टीचिंग इंटेसिव, तृतीय ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज, समग्र दृष्टिकोण से अंतर विशेष शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे स रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं मिलकर पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन में नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे स नई शिक्षा नीति 2020 के अंतरराष्ट्रीय करण की अगर बात करें तो, प्रत्येक संस्थान जो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों के लिए अलग से एक कार्यालय स्थापित करेगा स विश्व के 100 उच्च विश्वविद्यालय भारत में आ सकते हैं और भारत के उच्च संस्थान विदेश में अपना कैंपस खोल सकते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 का मूल्यांकन।

नई शिक्षा नीति 2020 में जहां एक और क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान हैस वहीं इसमें लगभग 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से और जुड़ जाएंगे स इससे अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात में काफी अंतर होगा स इसमें कोई शक नहीं है कि यह नीति विद्यार्थियों को एक दक्षता के साथ भविष्य के लिए तैयार करेगीस परंतु सवाल यह है कि जब बच्चे कक्षा 6 से इंटरशिप शुरू करेंगे,तब यह भी नीति में स्पष्ट होना चाहिए कि कहां पर, किन संस्थाओं में यह बच्चे जाएंगे?

नई शिक्षा नीति 2020 में सीखने की जो प्रवृत्ति है वह संपूर्ण रूप से एकीकृत,सभी विषयों का समावेश, सुखद और दिलचस्प है स यह समय की जरूरत के हिसाब से भी स्पष्ट दृष्टिकोण हैस लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषाओं में और आंगनवाड़ी में अपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे वे बच्चे उन बच्चों के सामने कमजोर साबित होंगे जो कान्वेंट या डीपीएस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे।

उच्च शिक्षा में जहां विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई एक साथ पूरी करने में अगर दिक्कत है तो वह बीच में छोड़कर फिर से वापसी कर सकते हैं यह सुविधा है स लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स से ही संतुष्ट होकर आगे पढ़ाई में अधिक रुचि ना दिखाएं जिससे उच्च शिक्षा का ग्राफ नीचे जा सकता है।

व्यवसायिक शिक्षा यह पद्धति कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देती है स इसका उद्देश्य छात्रों को प्रशिक्षित करके देश की अर्थव्यवस्था में उनके ज्ञान की भूमिका को बढ़ावा देता है।

अब प्रश्न यह भी है कि इसको लागू करने की रणनीति क्या हो सकती है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है,जैसे सभी अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी सभी को इस नीति का उद्देश्य और लक्ष्य भलीभांति अवगत होना चाहिए!

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए, ताकि शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित प्रभावी ढंग से किया जा सके स सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि संसाधनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी तक इनकी पहुंच हो स छात्रों को सीखने की प्रवृत्ति प्रदर्शन से संबंधित निरंतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता भी होगी स इसमें भी कोई शक नहीं है कि 2020 की शिक्षा प्रणाली पूर्णता परिवर्तन की ओर है लेकिन इस परिवर्तन में शिक्षकों को अपने भूमिका में बदलाव लाना होगा।

छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विषय विशेष ज्ञान से आगे बढ़कर अधिक सकारात्मक रुख रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा स फ़ैसिलिटेटर और मैटर के रूप में कार्य करना होगा स रचनात्मक और जिज्ञासा दोनों का दायरा बढ़ाना होगा, प्रौद्योगिकी के साथ अपने शिक्षण पद्धति को प्रखर करना होगा साथ ही स्थानीय संदर्भ में और संस्कृति को भी अपने स्वभाव में समावेश करना होगा।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 कुल मिलाकर इक्विटी और समावेशन अनुसंधान और नवाचार के बहू विषयक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यवसाय, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सारी चीजों को सामाजिक कल्याण, संज्ञानात्मक, बच्चों के समग्र विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा शिक्षा को रुचिकर बनाना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छात्रों को इस तरह से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटा जा सके स यह कहा जा सकता है कि फूलों के साथ कांटे अवश्य होते हैं लेकिन उनके के डर से फूलों की खुशबू को नहीं छोड़ा जा सकता है।

संदर्भ सूचि

1. Ritika Chopra, Explained Reading the new National Educational Policy, Archived the Indian Express, 2020.
2. PM Narendra Modi speech on New Education Policy to shift focus from" what to think and how to think, India Today,2020.
3. Nandini, (ed.) New Education Policy Highlights School and Higher Education to see Major Changes, Hindustan Times, Archived August 2, 2020.
4. Kasturirangen led panel to develop new curriculum for schools, Indian Express, 2021.
5. National Education Policy evokes mixed reactions among academician, Outlook India, 2020.
6. Amandeep Shukla, HRD begins process for creation of National Research Foundation, Hindustan Times,2020.
7. Samriti Malhotra, The Draft National Educational Policy, A distressing attempt to redefine India, Journal of Gujrat Research Society, 2019.
8. Draft NEP 2020 report, Minister of Human Resources Development.
9. Final NEP 2020 report, Ministry of Human Resources Development